मेहनतकशों का पैग़ाम
Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

नेट पर उपलब्ध :
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 R.N.I. No. 66400/97

दो शीर्ष भारतीय जिन्हें जेल में होना चाहिये : नवीन जिंदल और राबर्ट वाड्रा 3
घोटालेबाज सरकार का सुप्रीम कोर्ट क्या बिगाड़ लेगी 4
महिला विरुद्ध हिंसा और उसका तोड़ 6
मुख्यमंत्री को नहीं मिल रहा रामफल जैसा चापलूस लुटेरा वाइचांसलर 8

वर्ष 26 अंक 13 फरीदाबाद, वीरवार, 16-31 मई 2013 फोन : - 9999595632 सहयोग राशि 2 रुपया

डीसी की नाक तले लुटते

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले

फ़रीदाबाद (म.मो.) ज़िले के दो एसडीएम कार्यालयों-फरीदाबाद व बल्लबगढ़ में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का कार्य होता है। ड्राठविंग लाइसेंस कैसे बनेगा, कौन सा फ़ार्म लगेगा, कौन डाक्टरी परीक्षण करेगा, कौन टेस्ट लेगा और इन सब कामों की सरकार द्वारा कितनी फ़ीस ली जायेगी, यह सब भारत सरकार के - दि सेंट्रल मोटर व्हीकल रुल्स 1989 में स्पष्ट तौर पर वर्णित है। इसके बावजूद लाइसेंस आवेदकों से, रुल्स की अवहेलना करके कई गुणा अधिक पैसा जबरी वसूला जा रहा है।

रूल 32 में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि लर्नर लाइसेंस के लिये मात्र 30 रुपये लिये जायेंगे। परन्तु कोई भी लाइसेंस (बिना दलालों के) 400 रुपये से कम नहीं पड़ता। यदि दलालों के माध्यम से बनवाया जाये तो 200 रुपया और ज़्यादा लग सकते हैं। इस लाइसेंस के लिये सबसे पहले 25 रुपये का तो फ़ार्म व एक फ़ाइल कवर इसी कार्यालय से खरीदना अनिवार्य है जबकि इसकी वास्तविक कीमत 2 रुपया से अधिक नहीं होती। इसके बाद सौ रुपये की एक पर्ची पुलिस वालों द्वारा टेस्ट लेने के नाम पर काटी जाती है, सौ रुपये की एक और पर्ची डाक्टरी जांच के नाम पर

बलराज सिंह : उपायुक्त मस्त, जनता त्रस्त

भी काटी जाती है। यह जांच एसडीएम कार्यालया में बैठा एक व्यक्ति करता है। वह डाक्टर है या नहीं कोई नहीं जानता क्योंकि वह डाक्टरी जांच जैसा कोई काम नहीं करता

7 जांच के नाम पर वह केवल फ़र्म पर अपने दस्तखत करता है। इसके बाद सौ रुपये कम्प्यूटर फ़ीस व तीस रुपये कम्प्यूटर फ़ोटो के नाम पर वसूले जाते हैं। इसके बाद कहीं जा कर रूल 32 में लिखे वे 30 रुपये लिये जाते हैं जो सरकारी फ़ीस है।

इस लर्नर लाइसेंस के बाद जब पक्का लाइसेंस बनता है तो वही सारी उपरोक्त कवायद फ़िर से शुरू होती है। लेकिन इस बार आवेदन फ़ार्म व फ़ाइल कवर 25 रुपया की बजाये 10 रुपया का दिया जाता है। लेकिन इस बार एक और कहीं बड़ा धोखा लाइसेंस आवेदकों के साथ किया जाता है। सरकारी रुल्स के मुताबिक पक्का लाइसेंस दो तरह का होता है। फ़ार्म 6 द्वारा साधारण लाइसेंस की फ़ीस 40 रुपया तथा फ़ार्म 7 द्वारा कम्प्यूटराइज़्ड चिप वाले लाइसेंस की फ़ीस 200 रुपया निर्धारित की गयी है। चिप वाले लाइसेंस को कम्प्यूटर पर लगाते ही लाइसेंस धारक का सारा बही खाता (डाटा) स्क्रीन पर आ जाता है। यद्यपि यह व्यवस्था अभी चालू नहीं हुई है और न ही इसे चालू करना इस सरकार के बस का नजर आता है। परन्तु प्रत्येक लाइसेंस आवेदक से फ़ीस 200 रुपया ही वसूली जाती है बेशक यह फ़ीस सरकारी खजाने में जा रही है, लेकिन फ़िर भी आवेदक के साथ धोख-धड़ी तो डीसी की नाक तले दोनों एसडीएम कर ही रहे हैं।

शेष पेज 2 पर

बीके अस्पताल का एक्रेडेशन कराने के प्रयास में बाधक बनी सरकारी लूट

फ़रीदाबाद (म.मो.) हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की वित्तीय आयुक्त नवराज संधू ने गत पखवाड़े शहर के बादशाह खान सामान्य अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल की लचर-पचर व्यवस्था को देखकर संधू ने संबंधित डॉक्टरों एवं अधिकारियों को हमेशा की तरह अच्छा खासा हड़काया। इस तरह के हड़काने वाले अब तक कई आए और कई गए। डांट फटकार सुनने के आदी डॉक्टर एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। वे इन बातों को दिल पर नहीं लेते।

दौरे के दौरान संधू ने बताया था कि वे राज्य के 5 अस्पतालों को नेशनल एक्रेडेशन बोर्ड ऑफ़ हॉस्पिटल (एनएबीएच) से मान्यता दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। बादशाह खान अस्पताल भी उनमें से एक है। इसी उद्देश्य को लेकर वे पिछले करीब एक वर्ष से यदा-कदा अन्य अस्पतालों की तरह इस अस्पताल का भी निरीक्षण करने के बाद डॉक्टरों को फटकारती रहती हैं। फ़टकार के अलावा करोड़ों रुपए भी इस अस्पताल पर खर्च किए जा चुके हैं।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार गत् 2-3 वर्षों में उक्त 5 अस्पतालों को एनएबीएच की मान्यता दिलाने के नाम पर 75 करोड़ की विभिन्न मशीनें आदि लार्सेन एंड टुर्बो नामक कंपनी से ख़रीद कर डाल दी गई हैं। इसी खाते से यहाँ भी एक डायलेसिस मशीन, एंडोस्कोपी मशीन व लांड्री की मशीनें खरीदी गई थीं। इनमें से किसी भी मशीन का आज तक कोई इस्तेमाल न तो हुआ है और न ही होने की कोई संभावना है।

- शेष पेज 2 पर

उपलब्ध जानकारी के अनुसार गत् 2-3 वर्षों में उक्त 5 अस्पतालों को एनएबीएच की मान्यता दिलाने के नाम पर 75 करोड़ की विभिन्न मशीनें आदि लार्सेन एंड टुर्बो नामक कंपनी से ख़रीद कर डाल दी गई हैं। इसी खाते से यहाँ भी एक डायलेसिस मशीन, एंडोस्कोपी मशीन व लांड्री की मशीनें खरीदी गई थीं।

ख़बर दार

मनमोहन बाबा और सारे चोर

दिल्ली (म.मो.) अली बाबा और 40 चोरों की कहानी भारतीय जनमानस में इस कदर पैंठ कर चुकी है कि चोरों का हर गिरोह या तो खुद अपने लिये बाबा ढूंढ लेता है और या लोग उसे एक बाबा दे देते हैं। मनमोहन सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उनकी सरकार में काम करने वाला मन्त्री, अफ़सर, ओहदेदार एक एक कर चोर सिद्ध हो रहे हैं। राजा, पवन बंसल, अश्वनी कुमार तो चंद नंगे हो चुके उदाहरण हैं वरना हाल सभी का एक जैसा है। रेल मंत्री पवन बंसल के नाम पर पैसे ले रहे उसके भानजे के मामले में कांग्रेस की कोर-कमेटी ने मंत्री से इस्तीफ़ा लेना इस बहाने से टाल दिया कि अभी सीबीआई जांच पूरी नहीं हुई है। हांलाकि सच्चाई यह है कि कोर कमेटी का हर सदस्य बंसल वाले रास्ते पर ही चल रहा है। पूर्व संचार मंत्री राजा चीख-चीख कर कह रहा है कि

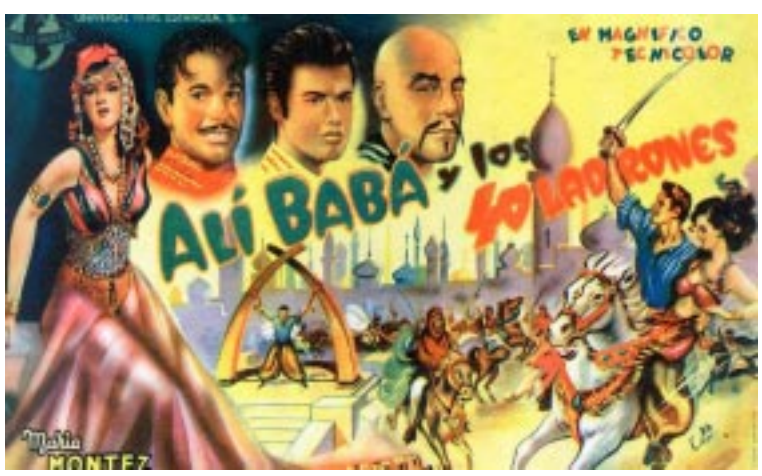

अली बाबा 40 चोर

पीएम और तत्कालीन वित्त मंत्री को समान रूप से संचार घोटाले का ज़िम्मेदार बनाया जाना चाहिये। सारी फ़ाइलें पीएमओ और वित्त मन्त्रालय में भी स्वीकृत हुई थीं, और यह तो सभी मानते हैं कि वित्तीय मामलों में मनमोहन सिंह और चिदम्बरम की अक्ल राजा से कई गुणा बढ कर है।

कोयला घोटाले में तो आंच सीधे मनमोहन सिंह पर ही आ रही है क्योंकि बीच-बीच में इस मंत्रालय का कार्यभार काफ़ी अर्से तक उनके पास रहा है। रक्षा मन्त्री ए के एंथोनी की ईमानदार छवि के बावजूद रक्षा सौदों में एक के बाद एक घोटाले बाहर आ रहे हैं। शरद पवार के व उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस के अन्य सहयोगी प्रफुल्ल पटेल तो क्रमश: कृषि एवं उड्डयन मंत्रालयों के भारी-भरकम घोटालों के टाइम-बम पर बैठे हैं। प्रमुख विश्वास पात्र मन्त्रीद्वय कपिल सिब्बल व सलमान खान जिन-जिन मंत्रालयों में रहे हैं, वहां मनमानी के घोटालों की पूरी कतार देखी जा सकती है। उच्च शिक्षा तो आज के दिन अपने आप में एक घोटाला है। क्या मनमोहन सिंह ऐसा कोई लेखा-जोखा रखते हैं कि उनके कितने मन्त्री व कितने अन्य ओहदेदार आपराधिक मामलों व आरोपों में लिप्त हैं। यह एक कठिन काम भी है। ज़्यादा आसान यह होगा कि प्रधानमंत्री ऐसे लोगों की लिस्ट बनायें जो अपराध के संदेह से परे हों। क्योंकि यह लिस्ट छोटी सी ही होगी। यहां तक कि इस छोटी सी लिस्ट में स्वयं मनमोहन सिंह का नाम भी नहीं होगा।

दरअसल मनमोहन सिंह एक ऐसा विरोधाभासी व्यक्तित्व है जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर चिपके रहने के लिये जनता, समाज, देश सभी का बिकना देख रहे हैं, कहते हैं कि वे स्वयं पूर्ण रूप से ईमानदार हैं। अगर ऐसा है तो उनके व्यक्तित्व का विरोधाभास और भी गहरा हो जाता है। एक व्यक्ति जो पूर्ण रूप से ईमानदार हो, उसकी सत्य-निष्ठा पूर्ण रूप से गायब कैसे हो सकती है? संभवत: वे सारी दुनिया में अकेले व्यक्ति होंगे जिनकी इमानदारी (ओनेस्टी) सौ प्रतिशत है पर सत्य-निष्ठा (इंटीग्रीटी) ज़ीरो प्रतिशत है। ऐसा हाल तो 40 चारों के अलीबाबा का भी नहीं था। इसीलिये मनमोहन सिंह सारे चोरों के मनमोहन बाबा बने हुए हैं।